इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तब रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जो एप्रिंटसेज होंगे उनमें से 50 परसेन्ट पोस्ट्स इनसे भरी जायेंगी। सभी मंत्रालयों की कैबिनेट तो एक ही होती है। रेलवे में इसको शुरू भी कर दिया गया है। यहां पर मंत्री जी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नही है जबकि लोक सभा में यह आश्वासन दिया गया था और उस पर अमल भी शुरू हो गया। अब एक मंत्री एक तरह से अमल करे और दूसरे दूसरी तरह से अमल करे—यह ठीक नही है, अगर कोई क्लियरकट पालिसी सरकार के सामने आये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री चिमन भाई एच० शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी सरकार की ओर से इस तरह की बात कहना कि आब्लीगेटरी नही है, कंपलसरी नही है—इस तरह की टेक्निकल बात कहना ठीक नही है। जहां तक मेरी इफार्मेशन है, कोई जगह जब खाली होती है तब उनको इंटर्व्यू तक के लिए भी नही बुलाया जाता है। एप्रेंटिसशिप योजना पर इतना रुपया खर्च करने के बाद सरकार यह कहे कि कोई आब्लीगेशन नही है, सर्विस नहीं दे सकते है—यह बात ठीक नही है। कम से कम उनको इन्टर्व्यू में तो बुलाया जाये, सर्विस देने की बात तो बाद मे आती है। क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह चीज इसलिए शुरू की गई थी कि कुछ इण्डिविजुअल्ज को ट्रेनिंग दी जाये ताकि वे बैटर-इक्विप्ड हो सकें, उनको नौकरी मिलने की सुविधा हो जाए। जहां तक प्रेसेज का ताल्लुक है, उनके लिए यह हिदायत दे दी गई है —

"The Directorate of Printing have issued instructions to the heads of Government of India Presses that for actual appointments, apprentices should get their names registered with the employment exchanges on completion of their training; and qualified apprentices are given preference over other candidates in the matter of employment."

Subletting of Government Quarters in D.I.Z. Area, New Delhi

*268. SHRI SHIV SAMPATI RAM: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether any survey was made in the Government quarters in D.I.Z. Area, New Delhi, to find out the number of allottees of these quarters who have fully or partially let out their quarters to others and also have let out the garages allotted to them;

(b) the particulars in this regard; and

(c) the action taken or proposed to be taken against the defaulters?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हा।

(ख) और (ग). वर्ष 1977–78 के दौरान डी० आई० जैड० क्षेत्र में दिसम्बर, 1977 तथा जनवरी, 1978 मे दो अकस्मात निरीक्षण किये गये थे।

निरीक्षण किये गये 30 मकानों में से 27 मकानों में उप-किरायेदारी नही पाई गई थी। एक मामले मे उप-किरायेदारी साबित नही हुई। दो अन्य मामलों में आगे जांच की जा रही है।

श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि डी० आई० जैड०

एरिया में कितने क्वार्टर्स हैं ? क्या मंत्री जी को यह भी मालूम है कि सैक्टर डी और ई में क्वार्टर्ज तो क्या, गैराज तक किराये पर दिए हुए हैं, कई दुकानें वहां पर चल रही हैं। इन में ज्यादातर एस्टेट आफिस के लोग हैं, जो यह समझते हैं कि जांच एस्टेट-आफिस वाले ही करेंगे और वे उनकी शिकायत कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वे भी उन्हीं के साथी हैं ? इस संबंध में आप द्वारा हुई जांच का ब्यौरा क्या है ?

श्री राम किंकर : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्वार्टर्ज कितने हैं ? इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है। यदि माननीय सदस्य कोई निश्चित सूचना दें तो हम उसकी जांच करवा लेंगे। एट-रेण्डम जो जांच हमारी तरफ से हुई--वह पहली जांच 23-12-77 को हुई थी, उस में सभी मकान कायदे में पाये गये, कोई सब-लेटिंग नहीं था। दूसरी जांच जनवरी में की गई, उन में दो केसेज सामने आये हैं, जिन में से एक पर अभी जांच चल रही है और कार्यवाही की जा रही है, दूसरे केस में भी एक्शन लिया जा रहा है।

श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या सरकार सभी कर्मचारियों से एफिडेविट दाखिल करायेगी और उसके बाद सी० बी० आई० द्वारा जांच करायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पुर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : सभी सरकारी कर्मचारी जानते हैं कि सब-लेटिंग का उन को अख्तियार नहीं है। शेअरिंग की कुछ कैटेगरीज हैं, जिस के लिए उन को अख्तियार है। जिस वक्त ये मकान दिये जाते हैं उसी वक्त तमाम फार्मल कार्यवाही पूरी करा ली जाती है।

SHRI K. GOPAL: This irregularity and immorality of sub-letting the quarters does not exist only in this particular area. The main thing exists in our own MPs' quarters. Will the hon. Minister tell us that when he starts any enquiry, he will do it right from us? Otherwise, we don't have any right preach to others when we don't practise it ourselves. The question should have been: "How many quarters have been sub-let in the MPs' quarters, and in the Government quarters? Will the hon. Minister tell us this?"

श्री सिकन्दर बख्त : माननीय सदस्य ने जिन मकानात का जिक्र किया, उन में ऐसे मकानात थोड़े हैं जो जनरल पूल में हैं, ज्यादातर मकानात लोक सभा पूल में हैं। उन की जांच पड़ताल जरूर करायेंगे।

Lecturers appointed in Delhi University during Emergency

*269. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received a demand for reviewing the appointments of lecturers in the colleges of Delhi University during Emergency;

(b) whether there is any proposal under Government's consideration to review such appointment;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether the University Grants Commission has asked the Delhi University to furnish the details of such appointments in each college during Emergency; and

(e) if so, the details of such appointments in each college?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) to (e). A statement is laid on the Table of the Sabha.